



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 2 अगस्त, 2003/11 श्रावण, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 अगस्त, 2003

संख्या एल० एल० आर०-डी०(६)-१२/२००३-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक १-८-२००३ को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, २००३ (२००३ का विधेयक संख्यांक ६) को वर्ष २००३ के अधिनियम

संख्यांक 6 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अन्वीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1-8-2003 की यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 24 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4 में,—

धारा 4 का संशोधन।

(i) उप-धारा 3 में,—

(क) “और राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी :”, शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “।” चिन्ह रखा जाएगा ; और

(ख) विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा ; और

(ii) उप-धारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“(3-क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, पार्षदों के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि व्यक्ति जिसने किसी नगर निगम का ठीक पूर्ववर्ती चुनाव लड़ा हो और हारा हो तो वह उस नगर निगम या किसी अन्य नगर निगम के पार्षद के रूप में, इसकी विद्यमान अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई पार्षद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारित करेगा, परन्तु इस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में यथा उपबन्धित निगम की अवधि से परे नहीं।

(3-ख) उप-धारा (3-क) में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट पार्षदों तथा आयुक्त को निगम की सभी बैठकों में उपस्थित होने तथा विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।”।

निरसन और
व्यावृत्ति।

3. (1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 का एतद्द्वारा 2003 का 3 निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 6 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL CORPORATION
(AMENDMENT) ACT, 2003

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 1-8-2003)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003.

Short title
and com-
mencement,

(2) It shall be deemed to have come into force on the 24th day of May, 2003.

12 of 1994

2. In section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994,—

Amendmen
of section 4

(i) in sub-section (3),—

(a) for the words and signs “and the State Government may, by notification, also nominate as Councillors, not more than three persons having special knowledge or experience of Municipal Administration:”, the sign “.” shall be substituted; and

(b) the existing proviso shall be deleted; and

(ii) after sub-section (3), the following new sub-sections shall be inserted, namely:—

“(3-A). The State Government may, by notification, nominate as Councillors not more than three persons having special knowledge or experience of municipal administration:

Provided that a person who contested and lost the immediately preceding election of any Corporation shall not be nominated by the State Government as a Councillor of that Corporation or any other Corporation during its existing term :

Provided further that a Councillor nominated under this sub-section whether before or after the commencement of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2003 shall hold office during the pleasure of the State Government, but not beyond the term of Corporation as provided for in sub-section (1) of section 5 of this Act.

(3-B). The nominated Councillors referred to in sub-section (3-A) and the Commissioner shall have the right to attend all the meetings of the Corporation and to take part in the discussion therein but shall not have any right to vote.”.

Repeal and
saving.

3. (1) The Himachal Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2003 is hereby repealed.

3 of 2003

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.